जगलों में आग से 42 लाख की क्षति

वनमंत्री दिनेश अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के जंगलों में आग से अब तक 4,093 हेक्टयेर वनक्षेत्र प्रभावित हो चुका है, जबकि कुल 1878 दुर्घटनाएं हुई हैं। इससे प्रदेश को लगभग 42.15 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि जंगल में आग की रोकथाम व नियंत्रण की दिशा में वन विभाग पूरी मुस्तैदी से जुटा है। सरकार ने इस कड़ी में फायर वाचर की संख्या को जरूरत के अनुसार दस हजार तक बढ़ाने की सहमति दी है। अग्नि सुरक्षा के साथ साथ जल संवर्द्धन आदि कार्यो के लिए विश्व बैंक पोषित योजना के तहत राज्य सरकार जल्द ही करीब 650 करोड़ की कार्ययोजना केंद्र सरकार को भेजेगी।

विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में वनमंत्री दिनेश अग्रवाल ने बताया कि दूसरे चरण में गत दो दिनों से उत्तरकाशी जैसे कुछ स्थानों पर जंगलों में आग की घटनाएं घटित हुई हैं, मगर इन वनक्षेत्रों में भी आग पर नियंत्रण कर लिया गया है। जंगल में आग से अब तक हुए नुकसान के आंकड़े जारी करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक राज्य को इससे लगभग 42.15 लाख रुपये की क्षति हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए वनों में आग के नियंत्रण की समीक्षा की जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में वन्यजीवों के पलायन करने की स्थिति में उनकी सुरक्षा के विशेष उपाय के निर्देश दिए गए हैं।

सिविल सोयम वनों व वन पंचायती वनों में अग्नि सुरक्षा के लिए डी.एम. से तालमेल करते हुए सचल दस्ते बनाने के निर्देश दिए हैं। वनक्षेत्रों से पिरूल का निस्तारण नालों व सड़कों पर करने को कहा गया है। साथ ही, वन विभाग को जल्द ही एक हजार अतिरिक्त जी.पी.एस. फोन खरीदने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान 53 दिनों में वनाग्धिन की अधिक घटनाएं हुई। वनों में आग की रोकथाम के साथ सरकार ने जल संवर्द्धन पर भी ध्यान केंद्रित किया है। पंचायतों की मदद से इसके लिए मनरेगा के तहत भी कार्य कराए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि एक हजार मीटर से अधिक ऊंचाई पर चीड़ नियंत्रण में पेश आ रही अड़चन के बारे में भी सरकार जल्द केंद्र के समक्ष पैरवी करेगी। साथ ही, विश्व बैंक पोषित 650 करोड़ की योजना के तहत बनने वाली कार्ययोजना में भी अग्नि सुरक्षा व जल संवर्द्धन के कार्यो को शामिल किया जाएगा। जल्द कार्ययोजना तैयार कर केंद्र को भेज दी जाएगी।

दैनिक जागरण (देहरादून), 19 May 2016